Ved International Journal of Arts, Commerce and Technology (VIJACT)
© VIJACT | Vol.2, Issue 6, Jun 2026, pp. 18-24 | ISSN: 3139-1656 (Online)
DOI: https://doi.org/10.65785/vijact.v2i6.53
Available online at: https://vijact.com/

भारत में बालिका शिक्षा का विकास: कस्तूरबा विद्यालय के संदर्भ में

विनोद कुमार यादव [1] एवं डॉ0 बुशरा अलवेरा [2]

[1] *शोध छात्र, शिक्षाशास्त्र विभाग, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत*
[2] *सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र विभाग, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत*

Article Info

Article history:
Received Jun 04, 2026
Accepted Jun 13, 2026
Published Jun 30, 2026

Keywords:
बालिका शिक्षा
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
लैंगिक समता
आवासीय विद्यालय
प्रतिधारण

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध-पत्र भारत में बालिका शिक्षा के क्रमिक विकास का अध्ययन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) योजना के विशेष संदर्भ में करता है। स्वतंत्रता के पश्चात महिला साक्षरता 1951 की 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत तक पहुँची, फिर भी वंचित वर्गों की बालिकाओं में लैंगिक असमानता बनी रही। इसी अंतर को पाटने हेतु 2004 में KGBV योजना आरंभ हुई। उद्देश्य के रूप में पत्र बालिका साक्षरता के दशकीय रुझान तथा KGBV के नामांकन, प्रतिधारण एवं अपव्यय का विश्लेषण करता है। प्रविधि द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक है, जिसमें जनगणना, UDISE, नीति आयोग तथा संसदीय आँकड़े (2025 तक) सम्मिलित हैं। परिकल्पना यह है कि आवासीय विद्यालय बालिकाओं के नामांकन व प्रतिधारण को बढ़ाते हैं। परिणाम दर्शाते हैं कि 2024-25 तक 5,639 KGBV में 7.58 लाख बालिकाएँ नामांकित हुईं तथा माध्यमिक प्रतिधारण कमजोर रहा। निष्कर्ष यह है कि KGBV ने पहुँच का विस्तार किया, परंतु अवसंरचना एवं प्रतिधारण की चुनौतियाँ शेष हैं।

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Corresponding Author:
विनोद कुमार यादव
Email: vinod22091988@gmail.com

1. प्रस्तावना:

शिक्षा किसी भी समाज के सामाजिक एवं आर्थिक रूपांतरण का सबसे सशक्त माध्यम है, और बालिका शिक्षा इस प्रक्रिया की धुरी मानी जाती है। ड्रेज एवं सेन के अनुसार भारत के विकास की दिशा बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वंचित समूहों, विशेषकर स्त्रियों, को शिक्षा के अवसर किस सीमा तक सुलभ होते हैं (ड्रेज एवं सेन, 2013)। स्वतंत्रता के समय भारत में महिला साक्षरता अत्यंत न्यून थी। भारत की जनगणना के आँकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता 1951 में मात्र 8.86 प्रतिशत थी, जो क्रमशः बढ़ते हुए 2001 में 54.16 प्रतिशत और 2011 में 65.46 प्रतिशत तक पहुँची (भारत की जनगणना, 2011)। इस प्रगति के बावजूद पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच का अंतर 2011 में भी लगभग 16.68 प्रतिशत बिंदु बना रहा, जो ग्रामीण तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक समुदायों में और भी अधिक था (सांख्यिकी मंत्रालय, 2016)।

बालिका शिक्षा केवल अक्षर-ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं अंतर-पीढ़ीगत प्रगति का आधार है। शिक्षित बालिकाएँ अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं तथा निर्णय-प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं (कौशिक आदि, 2024)। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता, बाल-विवाह, घरेलू श्रम, विद्यालय की दूरी तथा सुरक्षा-संबंधी चिंताएँ बालिकाओं को विद्यालय से दूर रखती रहीं। इन्हीं संरचनात्मक बाधाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका

विद्यालय (KGBV) योजना आरंभ की, जिसका लक्ष्य शैक्षिक रूप से पिछड़े विकासखंडों में वंचित वर्ग की बालिकाओं हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भी 2030 तक विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर शत-प्रतिशत सकल नामांकन एवं लैंगिक समता का लक्ष्य निर्धारित किया है (शिक्षा मंत्रालय, 2020)। ऐसे में यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या KGBV जैसी लक्षित आवासीय योजनाएँ वास्तव में बालिकाओं की पहुँच, ठहराव एवं उपलब्धि को बढ़ा पाई हैं। प्रस्तुत पत्र इसी प्रश्न की पड़ताल वास्तविक एवं नवीनतम आँकड़ों के आधार पर करता है, ताकि नीति-निर्माण हेतु प्रामाणिक आधार प्रस्तुत किया जा सके।

2. साहित्य समीक्षा

आवासीय शिक्षा को वंचित बालिकाओं के लिए एक वैकल्पिक क्षेत्र के रूप में देखने वाले अध्ययन बताते हैं कि घर एवं समुदाय की बाधाओं से दूर एक सुरक्षित वातावरण बालिकाओं की शैक्षिक निरंतरता को संभव बनाता है, यद्यपि इन विद्यालयों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में संवेदनशीलता की आवश्यकता बनी रहती है (राजेन्द्र एवं सरीन, 2021)। झा एवं सहयोगियों ने बहु-राज्यीय अध्ययन में पाया कि आवासीय रणनीतियाँ बालिकाओं के नामांकन, आत्मविश्वास एवं सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं, परंतु इनका दीर्घकालिक प्रभाव शिक्षण-गुणवत्ता एवं अनुवर्ती सहायता पर निर्भर करता है (झा आदि, 2016)। KGBV के क्षेत्रीय मूल्यांकनों से मिश्रित चित्र उभरता है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के अध्ययन में पाया गया कि KGBV बालिकाओं की शैक्षिक अभिप्रेरणा एवं अधिकार-जागरूकता तो बढ़ाते हैं, परंतु उच्च अपव्यय, अपर्याप्त अवसंरचना तथा सामाजिक बाधाएँ अब भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं (सचान एवं कुमार, 2025)। ओडिशा के मलकानगिरि जिले के प्रकरण-अध्ययन में अवसंरचना एवं कौशल-विकास सुविधाएँ संतोषजनक पाई गईं, किंतु विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाओं तथा पर्याप्त शिक्षकों का अभाव रेखांकित हुआ (दाश, 2026)। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अध्ययन में विद्यालय-प्रबंधन एवं भौतिक सुविधाओं की कमियों की ओर संकेत किया गया (राजू एवं सत्यनारायण मूर्ति, 2022)।

शैक्षिक उपलब्धि की दृष्टि से असम के नगाँव जिले के अध्ययन में KGBV की कक्षा नौ की बालिकाओं की गणित में अधिगम-उपलब्धि का विश्लेषण किया गया, जिसमें आवासीय सहायता को उपलब्धि का सहायक कारक माना गया (अहमद, 2023)। दूसरी ओर, अपव्यय के कारणों पर केंद्रित अध्ययन दर्शाते हैं कि ग्रामीण आदिवासी बालिकाओं में विद्यालय-त्याग का जोखिम सर्वाधिक होता है, जिसमें निर्धनता, घरेलू उत्तरदायित्व एवं अध्ययन में अरुचि प्रमुख कारण हैं (नायक एवं कुमार, 2022)। कर्नाटक के गुणात्मक अध्ययन में यह सामने आया कि निर्धनता तथा "शुद्धता" एवं विवाह से जुड़ी लैंगिक मान्यताएँ मिलकर किशोरी बालिकाओं को माध्यमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने की ओर धकेलती हैं, और अभिभावकों की शैक्षिक आकांक्षा ही ठहराव का निर्णायक कारक सिद्ध होती है (भट्टाचार्जी आदि, 2018)। समग्र रूप से उपलब्ध साहित्य यह सुझाता है कि KGBV ने हाशिये की बालिकाओं तक शिक्षा की पहुँच को निस्संदेह बढ़ाया है, परंतु अवसंरचना, शिक्षक-प्रशिक्षण, शैक्षिक सहायता एवं विशेषकर माध्यमिक स्तर पर प्रतिधारण की दिशा में निरंतर सुधार आवश्यक है। यहीं प्रस्तुत पत्र राष्ट्रीय स्तर के नवीनतम आँकड़ों को संगठित कर एक समेकित चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।

3. उद्देश्य

1. भारत में बालिका साक्षरता एवं विद्यालयी नामांकन के दशकीय रुझान का विश्लेषण करना।
2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के नामांकन, सामाजिक संरचना, प्रतिधारण एवं अपव्यय का (2025 तक के आँकड़ों के आधार पर) मूल्यांकन करना।

4. शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है तथा पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों का उपयोग करता है। चूँकि अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर बालिका शिक्षा एवं KGBV की प्रवृत्तियों का समग्र चित्र प्रस्तुत करना है, इसलिए प्राथमिक सर्वेक्षण के स्थान पर प्रामाणिक प्रकाशित स्रोतों को आधार बनाया गया है। अध्ययन का प्रतिदर्श राष्ट्रीय स्तर के अभिलेख हैं, जिनमें भारत की जनगणना (2011) के साक्षरता आँकड़े, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के प्रतिवेदन, यूडीआईएसई प्लस

(UDISE+) 2024-25 के नामांकन-अनुपात, नीति आयोग का KGBV मूल्यांकन प्रतिवेदन, समग्र शिक्षाध्शिक्षा मंत्रालय के दस्तावेज, तथा राज्यसभा में दिसंबर 2025 तक प्रस्तुत किए गए नवीनतम सरकारी आँकड़े सम्मिलित हैं। इनके साथ 2015 से 2025 के बीच प्रकाशित समकक्ष-समीक्षित शोध-पत्रों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन द्वारा किया गया। आँकड़ा-संग्रहण हेतु दस्तावेजी विश्लेषण का प्रयोग किया गया तथा संख्यात्मक आँकड़ों को तुलनात्मक सारणीयन में संगठित किया गया। विश्लेषण के लिए प्रतिशत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण एवं तुलनात्मक विधि का उपयोग हुआ। समय-सीमा 1951 से 2025 तक रखी गई, ताकि दीर्घकालिक प्रगति स्पष्ट हो सके। अध्ययन की सीमा यह है कि यह राष्ट्रीय/राज्य-स्तरीय समुच्चयित आँकड़ों तक सीमित है और इसमें विद्यालय-स्तरीय प्राथमिक अनुभव सम्मिलित नहीं हैं।

5. परिणाम

इस खंड में बालिका साक्षरता तथा KGBV से संबंधित वास्तविक आँकड़ों को छह सारणियों में प्रस्तुत कर प्रत्येक का सांख्यिकीय विश्लेषण किया गया है।

सारणी 1 भारत में महिला साक्षरता दर का दशकीय रुझान

वर्ष	महिला साक्षरता दर (%)
1951	8.86
1961	15.35
1971	21.97
1981	29.76
1991	39.29
2001	54.16
2011	65.46

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011 / सांख्यिकी मंत्रालय।

सारणी 1 दर्शाती है कि छह दशकों में महिला साक्षरता में लगभग 56.6 प्रतिशत बिंदु की उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1951 से 1981 तक वृद्धि अपेक्षाकृत मंद रही, किंतु 1991 के पश्चात गति तीव्र हुई। 2001 से 2011 के बीच लगभग 11.3 प्रतिशत बिंदु की वृद्धि सर्वाधिक रही, जो साक्षरता मिशन एवं सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों का परिणाम मानी जाती है। यह प्रवृत्ति बालिका शिक्षा की दिशा में निरंतर नीतिगत प्रयासों की सफलता को रेखांकित करती है।

सारणी 2: 2011 में साक्षरता दर में लैंगिक अंतर

संकेतक	प्रतिशत (%)
कुल साक्षरता	74.04
पुरुष साक्षरता	82.14
महिला साक्षरता	65.46
लैंगिक अंतर (प्रतिशत अंक)	16.68
सर्वाधिक महिला साक्षरता (केरल)	91.98
न्यूनतम महिला साक्षरता (राजस्थान)	52.66

स्रोत: भारत की जनगणना, 2011

सारणी 2 के अनुसार 2011 में पुरुष एवं महिला साक्षरता के बीच 16.68 प्रतिशत बिंदु का अंतर विद्यमान था। राज्यवार विषमता और भी स्पष्ट है, केरल में महिला साक्षरता 91.98 प्रतिशत थी, जबकि राजस्थान में मात्र 52.66 प्रतिशत, अर्थात लगभग 39 प्रतिशत बिंदु का अंतर। यह विषमता दर्शाती है कि राष्ट्रीय औसत के पीछे गहरे क्षेत्रीय एवं सामाजिक अंतर छिपे हैं, जिन्हें KGBV जैसी लक्षित योजनाएँ संबोधित करने का प्रयास करती हैं।

सारणी 3: KGBV योजना: राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय एवं नामांकन (2025) तक

संकेतक	मान
कुल स्वीकृत KGBV	5,639
क्रियाशील KGBV	5,269
गैर-क्रियाशील KGBV	370
नामांकन (2023–24)	6,91,304
नामांकन (2024–25)	7,58,000 (लगभग)

स्रोत: राज्यसभा में प्रस्तुत सरकारी आँकड़े (Ns=h, 2025) शिक्षा मंत्रालय।

सारणी 3 दर्शाती है कि दिसंबर 2025 तक देश में कुल 5,639 KGBV स्वीकृत थे, जिनमें 5,269 क्रियाशील एवं 370 अभी भी गैर-क्रियाशील थे। नामांकन 2023-24 के 6,91,304 से बढ़कर 2024-25 में लगभग 7.58 लाख हो गया, अर्थात एक ही वर्ष में लगभग 9.6 प्रतिशत की वृद्धि। यह वृद्धि योजना के विस्तार एवं माँग की पुष्टि करती है, यद्यपि लगभग 6.6 प्रतिशत विद्यालयों का गैर-क्रियाशील रहना क्रियान्वयन-अंतराल को उजागर करता है।

सारणी 4: KGBV में सामाजिक वर्ग अनुसार नामांकित बालिकाएँ (2024-25)

सामाजिक वर्ग	नामांकित बालिकाएँ	अनुमानित हिस्सा (%)
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	2,64,000	34.8
अनुसूचित जाति (SC)	2,06,000	27.2
अनुसूचित जनजाति (ST)	1,77,000	23.4
गरीबी रेखा से नीचे (BPL)	1,10,807	14.6

स्रोत: शिक्षा मंत्रालय, राज्यसभा (Ns=h, 2025)

सारणी 4 KGBV के सामाजिक समावेशन को स्पष्ट करती है। कुल नामांकित बालिकाओं में सर्वाधिक हिस्सा OBC वर्ग (34.8) का है, इसके पश्चात SC (27.2) ST (23.4) वर्ग आते हैं, जबकि शेष 14.6 प्रतिशत ST परिवारों से हैं। इस प्रकार लगभग 85 प्रतिशत नामांकन सामाजिक रूप से वंचित श्रेणियों से है, जो दर्शाता है कि योजना अपने मूल लक्षित समूह तक प्रभावी रूप से पहुँच रही है तथा सामाजिक समता के उद्देश्य की पूर्ति कर रही है।

सारणी 5: KGBV में प्रतिधारण एवं अपव्यय दर

संकेतक	2022–23	2023–24	2024–25
प्रतिधारण (कक्षा 6–8) (%)	76.4	78.9	84.2
प्रतिधारण (कक्षा 9–12) (%)	45.1	47.5	49.5
अपव्यय (मध्य स्तर) (%)	8.3	—	2.9
अपव्यय (माध्यमिक स्तर) (%)	12.6	—	6.6

स्रोत: राज्यसभा में प्रस्तुत सरकारी आँकड़े (Ns=h, 2025)।

सारणी 5 प्रतिधारण में सुधार की प्रवृत्ति दर्शाती है। मध्य स्तर (कक्षा 6-8) की प्रतिधारण दर तीन वर्षों में 76.4 से बढ़कर 84.2 प्रतिशत हो गई, जबकि माध्यमिक स्तर (कक्षा 9-12) पर यह 45.1 से बढ़कर भी मात्र 49.5 प्रतिशत रही। अपव्यय दर मध्य स्तर पर 8.3 से घटकर 2.9 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 12.6 से घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई। आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि माध्यमिक स्तर पर ठहराव अब भी सबसे कमजोर कड़ी है।

सारणी 6 विद्यालयी शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) एवं लैंगिक समता (2024-25)

स्तर	कुल GER (%)	बालिका GER (%)	बालक GER (%)
प्राथमिक (कक्षा 1–5)	90.9	—	—
माध्यमिक (कक्षा 9–10)	78.7	80.2	77.3
उच्चतर माध्यमिक (कक्षा 11–12)	58.4	60.9	56.2

स्रोत:UDISE+ 2024-25 (मेहता, 2025)।

सारणी 6 दर्शाती है कि प्राथमिक स्तर पर ळम्त् 90.9 प्रतिशत के साथ लगभग सार्वभौमिक है, परंतु माध्यमिक (78.7) एवं उच्चतर माध्यमिक (58.4) स्तर पर तीव्र गिरावट आती है। उल्लेखनीय है कि दोनों उच्च स्तरों पर बालिकाओं का ळम्त् बालकों से अधिक है (उच्चतर माध्यमिक में 60.9 बनाम 56.2), जिससे लैंगिक समता सूचकांक एक से ऊपर रहा। कुल नामांकन में बालिकाओं का हिस्सा 48.4 प्रतिशत है, जो लैंगिक समता की दिशा में ऐतिहासिक प्रगति को प्रतिबिंबित करता है। साथ ही, नीति आयोग के मूल्यांकन में भी इन्हीं प्रवृत्तियों की पुष्टि होती है (नीति आयोग, 2021)।

6. विवेचना

प्रस्तुत परिणाम अध्ययन के दोनों उद्देश्यों के साथ संगति रखते हैं। प्रथम उद्देश्य बालिका साक्षरता एवं नामांकन के दशकीय रुझान के संदर्भ में सारणी 1, 2 एवं 6 मिलकर एक स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करती हैं। महिला साक्षरता का 8.86 प्रतिशत (1951) से 65.46 प्रतिशत (2011) तक पहुँचना तथा अब विद्यालयी स्तर पर बालिकाओं का बालकों से आगे निकल जाना यह दर्शाता है कि पहुँच एवं नामांकन के मोर्चे पर भारत ने उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। यह उपलब्धि सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्तियों तथा KGBV जैसी लक्षित योजनाओं के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। फिर भी सारणी 2 की राज्यवार विषमता केरल एवं राजस्थान के बीच लगभग 39 प्रतिशत बिंदु का अंतर, यह स्मरण कराती है कि औसत आँकड़े गहरी क्षेत्रीय असमानताओं को ढक देते हैं।

द्वितीय उद्देश्य KGBV के नामांकन, सामाजिक संरचना एवं प्रतिधारण के संदर्भ में सारणी 3, 4 एवं 5 निर्णायक हैं। सारणी 4 स्पष्ट करती है कि लगभग 85 प्रतिशत नामांकन SC-ST एवं OBC वर्गों से है अर्थात योजना अपने लक्षित सामाजिक समूह तक प्रभावी रूप से पहुँच रही है। यह परिणाम उन अध्ययनों से मेल खाता है जो आवासीय शिक्षा को वंचित बालिकाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम मानते हैं, क्योंकि एक समुदाय-आधारित सहायक वातावरण ही उनकी शैक्षिक निरंतरता को संभव बनाता है (भुवानिया आदि, 2024)। तथापि सारणी 5 की सबसे महत्वपूर्ण चिंता माध्यमिक स्तर का कमजोर प्रतिधारण (लगभग 49.5) है, अर्थात माध्यमिक स्तर पर प्रवेश लेने वाली आधी से भी कम बालिकाएँ इसे पूर्ण कर पाती हैं। यह कमजोरी आकस्मिक नहीं है। शिक्षकों के दृष्टिकोण पर आधारित बहु-केंद्रीय अध्ययन बताते हैं कि बाल-विवाह, घरेलू उत्तरदायित्व, सुरक्षा-चिंता तथा माध्यमिक विद्यालयों की दूरी जैसे कारक किशोरी बालिकाओं को विद्यालय से बाहर धकेलते हैं (शर्मा आदि, 2023)। इन्हीं सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं के बीच शिक्षा को निर्णायक हस्तक्षेप माना गया है, क्योंकि शिक्षित बालिकाएँ अपने अधिकारों एवं संभावनाओं के प्रति अधिक सजग होती हैं तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठा पाती हैं (सिंह, 2026)। अतः KGBV की वास्तविक सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब वह बालिकाओं को मध्य स्तर से माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक तक सुगमता से आगे बढ़ा सके।

नीतिगत दृष्टि से इसका एक स्पष्ट निहितार्थ यह है कि KGBV को अब केवल पहुँच बढ़ाने वाली योजना से आगे बढ़कर गुणवत्ता एवं ठहराव सुनिश्चित करने वाली योजना के रूप में सुदृढ़ किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत सभी KGBV का कक्षा 12 तक उन्नयन, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की व्यवस्था, पर्याप्त एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति, तथा परामर्श-सेवाओं का विस्तार आवश्यक है (समग्र शिक्षा, अदिनांकित)। 370 गैर-क्रियाशील विद्यालयों को शीघ्र सक्रिय करना तथा झारखंड जैसे राज्यों में 50:1 के प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात

को सुधारना तत्काल प्राथमिकताएँ हैं। यदि इन सुधारों को संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाए, तो KGBV राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सार्वभौमिक एवं समतामूलक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

7. निष्कर्ष

भारत में बालिका शिक्षा ने स्वतंत्रता के पश्चात एक लंबी यात्रा तय की है, जहाँ महिला साक्षरता 1951 की 8.86 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हुई, वहीं अब विद्यालयी स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात कई स्तरों पर बालकों से भी आगे निकल चुका है। इस रूपांतरण में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की भूमिका विशेष रही है, जिसने 2025 तक देश भर में 5,639 विद्यालयों के माध्यम से लगभग 7.58 लाख वंचित बालिकाओं तक आवासीय शिक्षा पहुँचाई और उनमें से लगभग 85 प्रतिशत को सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से जोड़ा। तथापि अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि उपलब्धियों के साथ चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं, विशेषकर माध्यमिक स्तर का न्यून प्रतिधारण, गैर-क्रियाशील विद्यालय, अवसंरचना की कमी तथा प्रतिकूल छात्र-शिक्षक अनुपात। निष्कर्षतः, KGBV ने बालिका शिक्षा में पहुँच एवं समता का सशक्त आधार तैयार किया है, परंतु इसकी पूर्ण सार्थकता गुणवत्ता, प्रतिधारण एवं उन्नयन पर केंद्रित अगली पीढ़ी के सुधारों पर निर्भर करेगी। एक समावेशी एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु बालिका शिक्षा में यह निवेश अनिवार्य है।

Reference

[1]. वर्मन, एस. (2023). असम के नगांव जिले के छात्रावास में निवासरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की कक्षा नौ की बालिकाओं की गणित में अधिगम-उपलब्धि: एक प्रकरण-अध्ययन. *सृजनात्मक शोध-विचार की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका (IJCRT), 11*(3), i312–i320. https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2303987.pdf

[2]. कौशिक, डी., गर्ग, एम., मिश्रा, ए., एवं चौधरी, एस. (2024). भारत में लैंगिक समता एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शिक्षा: एक साधन के रूप में एक अवलोकन. *कृषि विस्तार एवं सामाजिक विकास की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, 7*(3), 342–346. https://doi.org/10.33545/26180723.2024.v7.i3d.453

[3]. छेत्री, एस. (2025, 10 दिसम्बर). कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन बढ़ा, पर उच्च कक्षाओं का प्रतिधारण मात्र 50%: सरकारी आँकड़े. *Careers360*. https://news.careers360.com/kasturba-gandhi-balika-vidyalaya-kgbv-retention-rate-50-pc-enrolment-education-ministry-sarva-shiksha-abhiyan-class-6-12-school

[4]. झा, जे., मेनन, जी., मिन्नी, पी., एवं शनमुग प्रिया, टी. (2016). *आवासीय विद्यालयीय रणनीतियाँ: बालिका शिक्षा एवं सशक्तिकरण पर प्रभाव* (कार्य-पत्र संख्या 10996). eSocialSciences. https://ideas.repec.org/p/ess/wpaper/id10996.html

[5]. ड्रेज़, जे., एवं सेन, ए. (2013). *एक अनिश्चित गौरव: भारत एवं उसके अंतर्विरोध*. प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस. https://doi.org/10.1515/9781400848775

[6]. दास, एन. (2026). कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थिति: एक प्रकरण-अध्ययन. *बहुविषयक शोध हेतु अंतरराष्ट्रीय पत्रिका*. https://www.ijfmr.com/papers/2026/2/71163.pdf

[7]. नायक, के. वी., एवं कुमार, आर. (2022). शिक्षा की खोज में: ग्रामीण भारत में कुछ आदिवासी बालिकाएँ क्यों पढ़ती रहती हैं और अन्य विद्यालय क्यों छोड़ देती हैं? *सामाजिक समावेशन अध्ययन पत्रिका*. https://doi.org/10.1177/09716858211064251

[8]. भट्टाचार्य, पी., आदि. (2018). किशोरी बालिकाओं के माध्यमिक विद्यालय-प्रतिधारण एवं अपव्यय के संदर्भ में शिक्षा, निर्धनता एवं "शुद्धता": दक्षिणी भारत के कर्नाटक से एक गुणात्मक अध्ययन. *PLOS ONE, 13*(9), e0202470. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0202470

[9]. भारत की जनगणना. (2011). *साक्षरता एवं शिक्षा-स्तर*. महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, भारत. https://censusindia.gov.in

[10]. भुवानिया, पी., मुखर्जी, ए., एवं स्वामीनाथन, एच. (2024). सशक्तिकरण के माध्यम से महिला शिक्षा: एक समुदाय-आधारित कार्यक्रम के साक्ष्य. *World Development Perspectives, 33*, 100569. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2023.100569

[11]. मेहता, ए. सी. (2025). *यूडाइस प्लस 2024–25 आँकड़ों का विश्लेषण*. Education for All in India. https://educationforallinindia.com/analysis-of-udise-2024-25-data-by-prof-arun-c-mehta/

[12]. राजू, टी. एस., एवं सत्यनारायण मूर्ति, आर. (2022). पूर्वी गोदावरी जिले में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के संचालन का अध्ययन. *शोध प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार हेतु अंतरराष्ट्रीय पत्रिका, 7*(8), 1218–1226. https://www.ijrti.org/papers/IJRTI2208197.pdf

[13]. राजेन्द्र, ए., एवं सरीन, ए. (2021). वंचित बालिकाओं हेतु आवासीय शिक्षा: एक वैकल्पिक क्षेत्र. *भारतीय लैंगिक अध्ययन पत्रिका, 28*(2), 188–208. https://doi.org/10.1177/0971521521997962

[14]. शर्मा, एस., त्रिपाठी, आर., सिंह, पी. एस. के., एवं मेहरा, एस. (2023). भारत में बालिकाओं के विद्यालय-त्याग पर शिक्षकों का दृष्टिकोण एवं उनकी शिक्षा हेतु सहायक कार्यवाहियाँ: एक बहु-केंद्रीय गुणात्मक अध्ययन. *भारतीय युवा एवं किशोर स्वास्थ्य पत्रिका, 10*(2). https://medical.advancedresearchpublications.com/index.php/IndianJYouthandAdolescentHealth/article/view/2088

[15]. शिक्षा मंत्रालय. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf

[16]. सचान, एस., एवं कुमार, ए. (2025). कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का बालिका शिक्षा एवं कल्याण पर प्रभाव: अमेठी जिले का एक अध्ययन. *सृजनात्मक शोध-विचार की अंतरराष्ट्रीय पत्रिका* (*IJCRT*), *13*(4), g792–g800. https://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2504797.pdf

[17]. समग्र शिक्षा. (n.d.). *कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय* (*KGBV*). शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. https://samagra.education.gov.in/kgbv.html

[18]. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय. (2016). *भारत में स्त्री एवं पुरुष 2016: अध्याय 3—साक्षरता एवं शिक्षा*. भारत सरकार. https://mospi.gov.in/sites/default/files/reports_and_publication/statistical_publication/social_statistics/WM16Chapter3.pdf

[19]. सिंह, एस. (2026). महिला सशक्तिकरण पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन. *Research Hub International Multidisciplinary Research Journal* (*RHIMRJ*), *13*(5), 8–15. https://doi.org/10.53573/rhimrj.2026.v13n05.002

Cite this Article:

विनोद कुमार यादव [1] एवं डॉ0 बुशरा अलवेरा, " भारत में बालिका शिक्षा का विकास: कस्तूरबा विद्यालय के संदर्भ में "*, Ved International Journal of Arts, Commerce and Technology (VIJACT), ISSN: 3139-1656 (Online), Volume 2, Issue 6, pp. 18-24, Jun 2026.*
Journal URL: https://vijact.com
DOI: https://doi.org/10.65785/vijact.v2i5.53